International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

अमेरिकी विदेश नीति में परिवर्तन और समकालीन बांग्लादेश: ट्रम्प युग और वर्तमान राजनीतिक-रणनीतिक संकट

प्रो॰ प्रीति अवस्थी[1], कविता[2]

[1]प्रोफेसर, पोलिटिकल साइंस, अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज , लखनऊ
[2]रिसर्च स्कॉलर, पोलिटिकल साइंस, लखनऊ विश्वविद्यालय

शोध सारांश

इस शोध अध्ययन में वर्तमान ट्रम्प युग में परिवर्तित अमेरिकी विदेश नीति तथा बांग्लादेश के बीच संबंधों का अध्ययन तथा विश्लेषण, वर्तमान बांग्लादेश के राजनीतिक-रणनीतिक संकट के संदर्भ में किया गया है| इसमें **विदेश नीति विश्लेषण** दृष्टिकोण के माध्यम से नेता नेतृत्व के स्वरूप, घरेलू राजनीतिक गतिशीलताओं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया है| **निर्भरता सिद्धांत** के माध्यम से अमेरिका-बांग्लादेश की असमान आर्थिक संबंधों, बदलती नेतृत्व का बांग्लादेश पर प्रभाव, निर्यात के लिए बांग्लादेश का अमेरिका पर निर्भरता का अध्ययन किया गया है| ट्रम्प की "अमेरिका फर्स्ट" की नीति के तहत बहुपक्षवाद के विरुद्ध अलगाववाद एवं संरक्षणवाद की नीति का प्रभाव दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों पर प्रमुख रूप से पड़ा है, जिसमें विशेष रूप से बांग्लादेश भी शामिल है| हिन्द महासागर के पूर्वोत्तर भाग में स्थित बंगाल की खाड़ी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो अमेरिका और चीन के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र हैं, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका का बांग्लादेश के प्रति सहयोगात्मक संबंध को भी बढ़ावा दिया जा रहा है| बांग्लादेश-अमेरिका के मध्य आर्थिक विषमता तथा शक्ति विषमता के कारण बांग्लादेश की निर्भरता अमेरिका पर बनी हुई है, और बांग्लादेश की हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में स्थित होने के कारण अमेरिका के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, जो अमेरिका के लिए द्विपक्षीय सहयोगात्मक संबंध को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं|

[1] Avadh Girls' Degree College, Lucknow (University of Lucknow)
[2] Research Scholar (University of Lucknow)

शब्द कुंजी: विदेश-नीति विश्लेषण, निर्भरता सिद्धांत, "अमेरिका फर्स्ट" नीति, संरक्षणवाद, अलगाववाद, बहुपक्षवाद, डोनरो सिद्धांत|

प्रस्तावना:

सन् 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संघर्ष के समय अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन स्वतंत्रता के चार महीने के अंदर ही अमेरिका ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी और धीरे-धीरे व्यापार से लेकर सुरक्षा तक प्रत्येक आयामों में अच्छे संबंध विकसित होने लगे| दोनों देशों द्वारा वार्षिक साझेदारी वार्ता की भी शुरुआत की गई हैं, जो ढाका और वाशिंगटन के संबंधों को मजबूत करता हैं| अमेरिका के उप-सहायक सचिव आफ़रीन अख्तर ने कहाँ है की बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी बन चुका है,और अमेरिका अगले 50 सालों में बांग्लादेश के साथ अधिक मजबूत संबंध देखता हैं| अमेरिकी राज्य विभाग(2023) के अनुसार,"बांग्लादेश आर्थिक, जलवायु, मानवीय और सुरक्षा प्राथमिकताओं के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय साझेदार हैं|" इससे इस बात की पुष्टि होती हैं की बांग्लादेश संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्यू महत्वपूर्ण हैं|[3]

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल में अपनी नीतियों- विशेषकर व्यापार, रक्षा, आप्रवासन तथा भू-राजनीति को लेकर वैश्विक निहितार्थों को ताजा कर दिया है| बांग्लादेश रणनीतिक रूप से एक दक्षिण एशियन राष्ट्र है| इस प्रकार का परिवर्तन यह मांग करती है की अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंध ध्यानपूर्वक और सक्रिय दृष्टिकोण के साथ रखे| जहां ट्रम्प का प्रथम कार्यकाल(2017-2021) "**अमेरिकी फर्स्ट**" सिद्धांत के अंतर्गत कूटनीति में एक **"लेन-देन आधारित(ट्रांस-सेक्शनल)** दृष्टिकोण लेकर आया था, वही उनकी पुनः वापसी ढाका के लिए मौजूद चुनौतियों को और गहरा कर सकती है तथा साथ ही कुछ नए अवसर उत्पन्न कर सकती हैं|[4]चुनाव अभियान के दौरान ट्रम्प ने राष्ट्रवादी "अमेरिकी फर्स्ट" विदेश नीति का वादा किया था| उन्होंने नाटो से बाहर निकलने की धमकी दी और यूरोपीय देशों को चेतावनी दी की अमेरिका अब उनकी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाएगा| उन्होंने यह भी कहां था की वे रूस को जो चाहे करने दे सकते हैं| सबसे महत्वपूर्ण बात यह हैं की उनकी प्रमुख नियुक्तियों और सलाहकार **उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था** और वैश्वीकरण के आलोचक रहे हैं| इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की

[3] Islam, M. S. (2023, June 7). Why does bangladesh matter to the united states? *THE FINANCIAL EXPRESS*. https://thefinancialexpress.com.bd/views/views/why-does-bangladesh-matter-to-the-united-states

[4] Hasan, R. A. (2025, January 21). Trump's america first doctrine and its ripple effects on bangladesh. *The Daily Star*. https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/trumps-america-first-doctrine-and-its-ripple-effects-bangladesh-3804376

बात नहीं है की 2024 का चुनाव जीतने के बाद ऐसी सुर्खियाँ देखने को मिली जैसे- "ट्रम्प उदार वैश्विक व्यवस्था को झटका देंगे" या "अमेरिकी दुनिया में अपनी नई भूमिका चुन रहे है|"[5]

पहले कार्यकाल के दौरान "अमेरिका फर्स्ट" की नीति के तहत कूटनीति का ट्रांस-सैक्सनल दृष्टिकोण के कारण पारंपरिक गठबंधनों और बहुपक्षवाद पर कम ध्यान दिया गया तथा व्यापक भू-राजनीतिक चिंताओं की तुलना में आर्थिक और व्यापार कूटनीति पर ज्यादा जोर दिया गया| विश्लेषकों का तर्क हैं बांग्लादेश पर इसका प्रभाव गंभीर हो सकता है, जहां हाल के वर्षों में अमेरिका के साथ स्थायी और सहयोगात्मक संबंध रहे है|[6]

प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के पंद्रह साल बाद शेख हसीना ने लोगों के विद्रोह के कारण इस्तीफा दे दिया| तत्पश्चात् सैन्य एवं विद्यार्थी विरोध के नेता के सहयोग से प्रोफेसर डॉ यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया| जहां अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण, शासन सुधारों और नागरिकों की सुरक्षा की अपील की वहीं अमेरिका ने मानवाधिकार उलँघनों और विपक्ष पर दमन के लिए हसीना सरकार की निंदा की, जबकि नागरिक प्रतिभागियों को अंतरिम सरकार गठित करने की अनुमति देने में संयम बरतने के लिए बांग्लादेश की सेना की सराहना की|[7] प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अमेरिका पर बांग्लादेश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया और यह भी आरोपित किया गया की शेख हसीना के देश से बाहर निकालने में अमेरिका की भूमिका हैं: **"यदि मैंने सेंट मार्टिन द्वीप और बंगाल की खाड़ी अमेरिका को सौंप दी होती, तो मैं सत्ता में बनी रह सकती थी|"** अमेरिका ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा बताते हुए खारिज कर दिया| एक प्रेस ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरीन जीन-पियरे ने स्पष्ट किया की, "हम मानते है की बांग्लादेश की सरकार का भविष्य बांग्लादेश की जनता को ही तय करनी चाहिए, और यही हमारा रुख हैं|" यह पहली बार नहीं है की सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका-बांग्लादेश संबंधों के विमर्श में सामने आया हो| वास्तव में, 2023 में हसीना ने घोषणा की थी की बांग्लादेश की संप्रभुता सर्वोपरि हैं और "मैं सेंट मार्टिन द्वीप को पट्टे पर देकर सत्ता में वापस नहीं आना चाहती|"[8]

बांग्लादेश के साथ अमेरिका का जुड़ाव ऐतिहासिक रूप से सुरक्षा सहयोग, विकास सहायता और शासन से संबंधित पहलों द्वारा परिभाषित रहा है| हाल के वर्षों में वाशिंगटन ने बांग्लादेश को अपने व्यापक हिन्द-

[5] Jasmin, I. A., & Hosen I. (2025). Trump 2.0: Redefining america's role in the global order. *Discover Global Society*. https://doi.org/10.1007/s44282-025-00281-7

[6] Mahmud, K. U. (2024). Will trump 2.0 change US policy towards bangladesh? *The Business, Dhaka, Bangladesh. SSRN*, 1-4. https://doi.org/10.2139/ssrn.5413874

[7] Mohsin, S. S., Ibnat A., & Jahan S. (2025). The trajectory of US-Bangladesh relations under the second trump administration. *ISDA*, *35*, 27-59. https://doi.org/0971-2550

[8] Sakhuja, D. V. (2025). *Bangladesh in the crosshair of big powers contestation*. REVA University. www.rewa.edu.in

प्रशांत ढांचे में शामिल करने के प्रयास के तहत लोकतान्त्रिक मानदंडों, श्रम अधिकारों और समुद्री सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है| इसमें कूटनीतिक दबाव, प्रतिबंध तंत्र, मानवाधिकार संबंधी विमर्श तथा ऐसे सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है, जिनका उद्देश्य अमेरिकी रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप संस्थागत सामंजस्य विकसित करना है| हालांकि अमेरिका की नीति केवल इन कठोर उपायों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अकादमिक साझेदारियाँ, सिविल सोसाइटी कार्यक्रम और एनजीओ आधारित पहल जैसे अपेक्षाकृत सहयोगात्मक साधन भी शामिल हैं, जिनका लक्ष्य नीतिगत विमर्श और अभिजात वर्ग की समझ को प्रभावित करना है|[9]

उत्तर-पूर्वी हिन्द महासागर में स्थित बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है, उसे न केवल भारत के लिए बल्कि चीन और अन्य देशों के लिए भी सैन्य और व्यापारिक उद्देश्यों से एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और भू-राजनीतिक साझेदार बनाता है| भारत के साथ लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करने वाला यह देश भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित है, भारत के मुख्य भू-भाग और उसके पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, तथा भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ता है| शेख हसीना के पतन के बाद नई दिल्ली ने दोनों देशों की सीमा पर सुरक्षा पहले से ही कड़ी कर दी हैं|[10]

इस समय बांग्लादेश मे राजनीतिक अस्थिरता, निहित सुरक्षा चुनौतियों और व्यापक कूटनीतिक दबाव के कारण वाह्य नीतियाँ परिवर्तित हो रही हैं| व्यापार प्राथमिकताओं, शासन अपेक्षा, सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दे प्रमुख महत्व रखते हैं, जो चल रही राजनीतिक और रणनीतिक संकट में योगदान को चिन्हित करते हैं| यद्यपि घरेलू राजनीतिक कारक बांग्लादेश की आंतरिक गतिशीलता में केन्द्रीय भूमिका निभाते हैं फिर भी बाहरी प्रभाव, विशेषकर अमेरिकी विदेश नीति में होने वाले परिवर्तन ने देश के रणनीतिक परिवेश और उसकी विदेश नीति के विकल्पों को नए सिरे से आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं|

यह शोध ट्रम्प प्रशासन के तहत अमेरिकी विदेश नीति में आए परिवर्तन का समकालीन बांग्लादेश पर पड़े प्रभावों तथा उसके वर्तमान राजनीतिक-रणनीतिक संकटों में उसके योगदान का विश्लेषण करता हैं| वाशिंगटन में नेतृत्व-प्रेरित नीतिगत बदलावों को एक विकासशील राज्य की संरचनात्मक कमजोरियों से जोड़ते हुए, यह अध्ययन दक्षिण एशिया में महाशक्तियों की विदेश नीति में होने वाले परिवर्तनों और राजनीतिक स्थिरता के बीच की अंतःक्रिया को सूक्ष्म और संतुलित रूप में समझने का प्रयास करता है| इस विश्लेषण का मार्गदर्शन विदेश नीति विश्लेषण और निर्भरता सिद्धांत के सैद्धांतिक दृष्टिकोण करते

[9] Ahmed M. (2025). Bangladesh at the crossroads of US-China strategic rivalry: A deep state and hegemonic influence perspective. *SSRN*. https://doi.org/10.2139/ssrn.5815904

[10] Datta S. (2024, august7). *What are the ramifications of bangladesh's political turmoil for india, broader region?* Asia Pacific Foundation of Canada. https://www.asiapacific.ca/publication/explainer-bangladeshs-popular-uprising-creates-political-uncertainty

हैं, जो संयुक्त रूप से अमेरिकी नीति परिवर्तन के स्रोतों तथा बांग्लादेश पर पड़ने वाले उसके असमान और असंतुलित प्रभावों का आकलन करने के लिए एक सुदृढ़ रूपरेखा प्रदान करते हैं|

सैद्धांतिक ढांचा:

यह अध्ययन **विदेश नीति विश्लेषण** और **निर्भरता सिद्धांत** के माध्यम से ट्रम्प प्रशासन के विदेश नीति में होने वाले परिवर्तनों एवं इसका वर्तमान बांग्लादेश के राजनीतिक-रणनीतिक संकट पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है| ये दोनों सैद्धांतिक रूपरेखाएं मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका में नीति-परिवर्तन की उत्पत्ति तथा असमान वैश्विक संरचनाओं में निहित किसी विकासशील राज्य पर उसके असंतुलित प्रभावों को बहु-स्तरीय दृष्टिकोण से समझने में सक्षम बनाती हैं| जहां विदेश नीति विश्लेषण अमेरिका के भीतर नेतृत्व, घरेलू राजनीतिक गतिशीलताओं और संस्थागत निर्णय-प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं निर्भरता सिद्धांत बांग्लादेश के राजनीतिक और रणनीतिक व्यवहार को आकार देने वाली संरचनात्मक कमजोरियों और प्रतिबंधों को उजागर करता है| इन दोनों दृष्टिकोणों का समेकन इस अध्ययन को यह क्षमता प्रदान करता है की वह किसी महाशक्ति में नीति-निर्माण की प्रक्रिया को एक परिधीय राज्य पर पड़ने वाले उसके दीर्घकालिक और गहरे प्रभावों से जोड़कर समझा सके|

विदेश नीति विश्लेषण दृष्टिकोण: विदेश नीति विश्लेषण अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में विभिन्न अभिकर्ताओं - मुख्यतः राष्ट्र-राज्यों के बीच संबंधों और व्यवहार का अध्ययन है| इसमें कूटनीति, खुफियाँ गतिविधियों, व्यापार वार्ताएं तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे तत्व शामिल होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय अभिकर्ताओं के बीच विदेश नीति की वास्तविक तत्व को आकार देते हैं| इस क्षेत्र के केंद्र में निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है, अर्थात कौन निर्णय लेता है, वह व्यक्ति कौन हैं, किन परिस्थतियों में निर्णय लिए जाते हैं, और उन निर्णयों के क्या परिणाम होते हैं| इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए, विदेश नीति विश्लेषण केवल राज्य की औपचारिक निर्णय-निर्माण संरचना में शामिल अभिकर्ताओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उन विविध उप-राष्ट्रीय स्रोतों को भी ध्यान में रखता है जो किसी राज्य की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं|[11]

विदेश नीति लोक नीति का एक स्वरूप है, जिसे राज्य द्वारा योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया जाता और लागू किया जाता है| यह राज्य प्राधिकरण का एक निर्णय भी होती है तथा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में किसी निश्चित समय पर उत्पन्न किसी समस्या के प्रति अन्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विषयों के संदर्भ में राज्य की प्रतिक्रिया को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और पूर्ति करना होता है| विदेश नीति के अध्ययन में, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं द्वारा अक्सर एक महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित

[11] Alden, C. & Aran, A. (2011). Foreign policy analysis – an overview. In: Foreign Policy Analysis: New Approaches. (pp. 1-14). Routledge. ISBN 9780203640999)

किया जाता है- विदेश नीति विश्लेषण ताकि किसी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विषय द्वारा अपनाई गई नीति की बेहतर और यहाँ तक की उसकी प्रकृति की स्पष्ट समझ विकसित की जा सके| इसका उद्देश्य नीति को एक स्वतंत्र,आत्मनिर्देशित, गैर-रूढ़िवादी, निष्पक्ष तथा एकांगी दृष्टिकोण से परे जाकर समग्र और वस्तुनिष्ठ रूप में समझना होता हैं|[12]

अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से अदारवाद का समर्थक रहा है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के प्रस्तावों का विरोध करता आया है| उसके नेताओं ने सामान्यतः संरक्षणवादी नीतियों का विरोध किया है और कम व्यापार शुल्क को व्यापारिक साझेदारों को आकर्षित करने के एक साधन के रूप में अपनाया है| इसके माध्यम से अमेरिका ने न केवल वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित किया, बल्कि अपनी आर्थिक और राजनीतिक प्रभुता का भी विस्तार किया है| डोनाल्ड ट्रम्प का दूसरी बार चुना जाना इस निरन्तरता के संकेतों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ| यह सही है की ट्रम्प की पहली राष्ट्रपति अवधि ने बहुपक्षवाद को कमजोर और मुक्त व्यापार को बाधित कर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर प्रभाव डाला था, लेकिन अपने पहले कार्यकाल में उन्हें अपनी ही राजनीतिक परिधि के भीतर वांछित परिवर्तनों के प्रति कड़ा विरोध झेलना पड़ा| हालांकि, उनका दूसरा कार्यकाल उसी प्रतिरूप का अनुसरण नहीं करता| चुनाव अभियान के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी की दिशाहीनता और स्विंग राज्यों में ट्रम्प की जीत ने उन्हें लगभग अर्ध-निरंकुश सत्ता के साथ शासन करने की वैधता प्रदान कर दी है| इससे उन्हें अमेरिकी विदेश नीति की परंपराओं और सिद्धांतों दोनों को चुनौती देने का अवसर मिला| उनकी विदेश नीति दृष्टिकोण इस विश्वास पर केंद्रित है की विश्व में अमेरिका की केन्द्रीय भूमिका को देखते हुए वह दूसरों पर अपनी शर्ते थोप सकते है| इस बार ट्रम्प ने उदारवाद के स्पष्ट रूप से विरोध में रुख अपनाया है, जिसे अनेक धूर-दक्षिणपंथी विचारक खुल कर प्रकट करना भी पसंद नहीं करते| उन्होंने संरक्षणवादी नीति लागू की है और अन्य देशों पर शुल्क लगाए हैं, चाहे वे अमेरिका के घनिष्ट सहयोगी ही क्यों न हो|[13]

राष्ट्रपति ट्रम्प के पहले प्रशासन ने “अमेरिका फर्स्ट” की नीति अपनाई, जिसमें अमेरिकी संप्रभुता, आर्थिक राष्ट्रवाद और वैश्विक संघर्षों में कम हस्तक्षेप पर जोर दिया गया था| अन्य राष्ट्रपतियों ने भी अमेरिकी वर्चस्व को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, यह मानते हुए की इसे पहुपक्षवाद का नेतृत्व करके सबसे अच्छी तरह हासिल किया जा सकता हैं| दूसरे कार्यकाल में, ट्रम्प प्रशासन के दृष्टिकोण और कार्य-शैली को विदेश नीति की प्राथमिकताओं को एक अधिक व्यापक और सुव्यवस्थित समूह में रूपांतरित किया गया हैं, जिनमें शामिल हैं:

[12] Hong, D. L. T. (2022). Foreign policy analysis - an approach from policy theory. *Migration Letters*, *19*, 1656-1665.
[13] Saraiva, M. G. (2025, May 8). *Donald trump's foreign policy: A view from the global south*. GATE Center. https://gatecenter.org/en/donald-trumps-foreign-policy-a-view-from-the-global-south/

1. अंतरराष्ट्रीय संबंधों में **द्विपक्षीय लेन-देन आधारित दृष्टिकोण(बाइलैटरल ट्रांस-सेक्शनलिज़म)** पर विशेष जोर देना- जिसका प्रमाण सऊदी अरब में अमेरिका-रूस के बीच यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने को लेकर हुई बैठक से मिलता हैं, जिसमें न तो यूक्रेन और न ही किसी यूरोपीय देशों की भागीदारी थी|
2. अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से पीछे हटना और उन्हें प्रभावी रूप से कमजोर करना- जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और UNRWA से दूरी बनाना, तथा कार्यकारी आदेश 14155 और 02504 के तहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटना|
3. अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों को त्यागना और उन्हें कमजोर करना- जिसमें नाटो के अनुच्छेद 5 पर संदेह व्यक्त करना तथा कार्यकारी आदेश 02010 के तहत पेरिस समझौते से बाहर निकलना शामिल है|
4. शुल्क के माध्यम से आर्थिक दबाव डालना- जिसे अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है| अब तक यह कनाडा, मैक्सिको और चीन के विरुद्ध कार्यकारी आदेश 02406, 02407 और 02408 के तहत लागू किया गया है|
5. मित्र देशों के क्षेत्रों की संप्रभुता को लेकर आक्रामक बयान देना तथा उन्हें अधिग्रहण करने या पुनः प्राप्त करने का लक्ष्य रखना तथा अमेरिकी नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए अन्य पक्षों को हटाने तथा अपने प्रभाव- क्षेत्र के विस्तार का प्रयास करना- जिसका प्रमाण एजेन्डा 47 के तहत नाटो के पुनर्मूल्यांकन और पनामा नहर, कनाडा तथा ग्रीनलैंड को अधिग्रहित करने संबंधित बयानों से मिलता है|
6. सीमा सुरक्षा में वृद्धि- जिसे कार्यकारी आदेश 02015 और 02089 में दर्शाया गया है, जो आप्रवासन के प्रति अधिक कठोर रुख को संकेतित करते हैं|
7. अमेरिकी प्राथमिकताओं में बदलाव- जिसमें रूस के प्रति रुख को मृदु करना और इसके विपरीत चीन के प्रति कठोर रुख अपनाना शामिल है| यह राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रत्यक्ष संवाद तथा चीन पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से स्पष्ट होता है|[14]

राष्ट्रपति ने कथित रूप से भ्रष्ट अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के विरुद्ध तीखा आक्रोश व्यक्त किया है, जिसके बारे में उनका दावा है की उसने अमेरिका को ठगा है, और उन्होंने दोषी देशों पर एकतरफा रूप से शुल्क लगाने के लिए कार्यकारी अधिकार का दावा किया है| उनके प्रशासन ने अमेरिकी शक्ति को पश्चिमी गोलार्द्ध तक विस्तारित किया, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादूरों का अपहरण करना और देश के तेल पर दावा करना, मैक्सिको की खाड़ी का नाम एकतरफा रूप से बदलकर “अमेरिका की

[14] https://share.google/7mtTk4WAH24Ca6thD

खाड़ी" रखना, तथा पनामा नहर पर अमेरिकी नियंत्रण की पुनः पुष्टि करना शामिल है| इसने लोकतंत्र के प्रसार और मानवाधिकारों को कम महत्व दिया है तथा बहुपक्षीय संस्थानों से पीछे हट गया है|[15]

बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश की रणनीतिक स्थिति और चीन की बेल्ट एंड रोड इनीसीटिव(BRI) में उसकी भागीदारी उसे दक्षिण एशिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है| ट्रम्प 2.0 के तहत, अमेरिका द्वारा चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के प्रयासों में तेजी लाए जाने की संभावना है, जिससे बांग्लादेश के सामने जोखिम और अवसर दोनों उत्पन्न होंगे| एक ओर वाशिंगटन ढाका के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने का प्रयास कर सकता है; दूसरी ओर, अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता बांग्लादेश के चीन के साथ संबंधों पर दबाव डाल सकती है, जो उसका एक प्रमुख व्यापारिक और बुनियादी ढांचा विकास साझेदार है|[16]

निर्भरता सिद्धांत: पॉल प्रेबिस पहले विद्वान थे जिन्होंने 1950 के दशक में निर्भरता सिद्धांत का प्रस्ताव रखा| यह सिद्धांत उनके स्वयं के शोध निष्कर्षों पर आधारित था| 1930 के दशक की वैश्विक आर्थिक मंदी तथा उनके अपने देश(अर्जेन्टीना) के सामने मौजूद आर्थिक समस्याएं प्रेबिस के अध्ययनों की पृष्टभूमि बनी| उनके शोध मुख्य रूप से आर्थिक वृद्धि और विकास से जुड़ी समस्याओं पर केंद्रित थे|[17] निर्भरता की एक प्रायः उद्धृत परिभाषा डोस सैंटोस द्वारा दी गई है| उनके अनुसार यह वह स्थिति है, "जिसमें कुछ देशों की अर्थव्यवस्था का स्वरूप किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार द्वारा निर्धारित होता है|" इस परिभाषा के केंद्र में, केंद्र और परिधि अथवा परिधियता का भेद निहित है, जो यह दर्शाता है की अपेक्षाकृत कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा होने से कुछ संरचनात्मक सीमाएं जुड़ी होती हैं| यह भेद सबसे पहले प्रेबिस ने 1944 में दिए गए एक व्याख्यान में प्रस्तुत किया था| इसके अतिरिक्त, डोस सैंटोस(1970) ने इस बात पर भी बल दिया की निर्भरता के विभिन्न रूप केवल अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे उत्पादन की आंतरिक संरचनाओं तथा उनसे संबंधित सामाजिक और राजनीतिक ढांचों से भी जुड़े होते हैं|[18]

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में हुए परिवर्तनों के कारण निर्भरता सिद्धांत की लोकप्रियता में भले ही कमी आई हो, फिर भी इक्कीसवीं सदी की वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में राज्यों के बीच आर्थिक और शक्ति-

[15] Reiss, A. M. (2026, January 20). *Trump's foreign policy after year one: A look back, a look ahead*. Rusi.org. https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/trumps-foreign-policy-after-year-one-look-back-look-ahead

[16] Obaidullah M. (2024, December 30). *Trump 2.0 and bangladesh 2.0: Redefining dynamics in a new era of bilateral relations- analysis*. Eurasiareview.com. https://share.google/FA7ks6v3G0MkIqEPv

[17] Asuquo, E. E., Deborah A., & Jason emeka U. (2024). Dependency theory and development policy in a 21st century context. *Journal of Political Discourse*, (4). https://www.researchgate.net/publication/388106151_DEPENDENCY_THEORY_AND_DEVELOPMENT_POLICY_IN_A_21ST_CENTURY_CONTEXT

[18] Kvangraven, I. H. (2020). Beyond the stereotype: Restating the relevance of the dependency research programme. *Development and Change*, *52*(1), 76-112. https://doi.org/10.1111/dech.12593

संबंधों को समझाने में यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक बना हुआ है| वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण देशों के बीच मौजूद असमान और शोषणकारी संबंधों की अभिव्यक्ति कई क्षेत्रों में देखी जा सकती है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक क्षेत्र शामिल हैं|[19]

संयुक्त राज्य अमेरिका से चीन की ओर वैश्विक आर्थिक शक्ति के स्थानांतरण को लेकर बहस लगातार जारी है, फिर भी बांग्लादेश सहित विकासशील देशों के लिए अमेरिका का योगदान अब भी महत्वपूर्ण बना हुआ है| प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(FDI), प्रेषण(रेमिटेन्स) तथा अन्य प्रकार की सहायता के लिए विकशीत देशों, विशेष रूप से अमेरिका पर बांग्लादेश की आर्थिक निर्भरता अच्छी तरह स्थापित तथ्य है| अमेरिका और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय से ही चले आ रहे हैं और इन संबंधों ने एक सहायक गठबंधन को जन्म दिया है, जिसके महत्वपूर्ण आर्थिक निहितार्थ हैं|[20] दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध अब भी मजबूत हैं और लगातार बढ़ रहे हैं| संयुक्त राज्य अमेरिका बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा है, विशेष रूप से वस्त्र और परिधान(टेक्सटाइल और गार्मेंट्स) के क्षेत्र मे; हालांकि हाल के वर्षों में, संबंधों में तनाव आने के कारण इसमें धीरे-धीरे गिरावट देखि गई है|[21]

बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था और विकास के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर बना हुआ है, और यह निर्भरता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है| ऐसा इसलिए है क्योंकि वह 2026 तक "अल्पविकसित देश" की श्रेणी से बाहर निकलकर एक "उच्च माध्यम आय वाला देश" बनने की आकांक्षा रखता है| इसी समय, अमेरिकी कंपनियां, उनके सहयोगी और साझेदार, बांग्लादेश के बाजार में निवेश करने के लिए लगातार अधिक रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने अमेरिकी निजी क्षेत्र के लिए अनुकूल वातावरण और स्वीकार्यता प्रदर्शित की है| इसके अतिरिक्त, अमेरिका बांग्लादेश को अपनी "**हिन्द-प्रशांत रणनीति**" का एक केंद्रबिन्दु मानता है| इसका कारण बंगाल की खाड़ी में उसकी भू-रणनीतिक स्थिति है, जो हिन्द-प्रशांत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तथा उसकी बढ़ती हुई आर्थिक क्षमता भी है|[22]

ट्रम्प की ट्रांस-सैक्सनल कूटनीति भले ही सॉफ्ट पावर से जुड़ी पहलों को कमजोर कर दे, लेकिन अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के बीच बांग्लादेश के लिए निर्यात के नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, विशेषकर रेडिमेंट गार्मेंट्स(RMG) के क्षेत्र में| चीनी वस्तुओं पर लगाए गए उच्च शुल्क बांग्लादेशी निर्यात को लाभ पहुँचा सकते हैं, हालांकि व्यापक संरक्षणवादी नीतियाँ इन संभावित लाभों को कमजोर भी कर सकती हैं|

[19] Oyetunde, O. S. (2022, August 17). *Is dependency theory relevant in the twenty-first century?* E-Ir.Info. https://share.google/SUAv3NYCFqQMYPZNt

[20] Ahmed Z., Habib, M. A., & Khan , S. R., opee (2023). The economic contributions of usa to bangladesh: An evaluation of bilateral relations over 50 years. *Bangladesh Journal of Integrated Thoughts*. https://doi.org/10.52805/bjit.v19i1.295

[21] Banerjee, D. S. (2024, September 10). *The shift in us-bangladesh relations*. Icwa.in. https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=11768&lid=7167

[22] Bose S. (2023, May 29). *A hitch in bangladesh-US relations?* https://www.orfonline.org/expert-speak/a-hitch-in-bangladesh-us-relations

2022 में 354 मिलियन डॉलर से घटकर 2023 में 314.9 मिलियन डॉलर तक अमेरकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आई गिरावट यह दर्शाती हैं की बांग्लादेश को एक अधिक निवेश-अनुकूल वातावरण विकसित करने की आवश्यकता है| माल निर्यात का 84.7% हिस्सा रखने वाला RMG क्षेत्र केवल सस्ते उत्पादन तक सीमित न रहकर मूल्य-संवर्धित उत्पादों और ब्रांडिंग रणनीतियों की ओर बढ़े, यह अत्यंत आवश्यक है| साथ ही, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, औषधि और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों का विस्तार आर्थिक जोखिमों को कम करने में सहायक होगा और बांग्लादेश की विकास संभावनाओं को अधिक संतुलित और टिकाऊ बनाएगा|

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में सहायता(ऐड) को फ्रिज करने का निर्णय ने पूरे दक्षिण एशिया में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं| बांग्लादेश जैसे देशों के लिए, जो पहले से ही आर्थिक नाजुकता से जूझ रहे हैं, यह कदम एक गंभीर खतरे के रूप में सामने आया है और इससे उसकी राजनीतिक तथा सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ और अधिक गहरी हो सकती हैं| इस निर्णय के प्रभाव दूरगामी हैं, विशेषकर शरणार्थी प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थय, स्वच्छता तथा स्वच्छ पेयजल तक पहुँच जैसे क्षेत्रों में| बांग्लादेश लंबे समय से सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों सहित कई तात्कालिक समस्याओं से निपटने के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर रहा है| इस प्रयासों में अग्रणी संस्थानों में से एक है इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरीयल डिजीज रिसर्च, बांग्लादेश(ICDDR,B) जिसने चिकित्सा अनुसंधान और रोग-निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है| हालांकि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण ICDDR,B को हाल ही में 1,200 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा है, जिनमें अनेक उच्च प्रशिक्षित शोधकर्ता और वैज्ञानिक शामिल हैं| दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है की बांग्लादेश के पास वर्तमान में इन अधिकांश विशेषज्ञों को वैकल्पिक भूमिकाओं में समाहित करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है| इससे देश में “ब्रेन ड्रेन” (प्रतिभा-पलायन) का खतरा बढ़ रहा है और अनुसंधान तथा स्वास्थय सेवा क्षेत्रों में एक बड़ा झटका लग सकता है| इसके अतिरिक्त, सहायता पर लगी रोक का महिलाओं के सशक्तिकरण, मानवाधिकार पहलों तथा देश के समग्र विकास पर भी असमान रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है, जिससे बांग्लादेश की विकास प्रक्रिया और अधिक बाधित हो सकती है|[23]

राष्ट्रपति ट्रम्प के अनुसार “टैरिफ(शुल्क) शब्दकोश का सबसे सुंदर शब्द है|” अपने पूरे राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान ट्रम्प ने वादा किया था की वे शुल्क को अपनी विदेश नीति की रणनीति का एक केन्द्रीय उपकरण बनाएंगे| उनका “अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी” संबंधी ज्ञापन भी प्रशासन को निर्देश देता

[23] Antora, A. R., & Muntasir T. (2025, November 2). *US foreign policy shifts and their impact on bangladesh and south asia's political landscape*. https://share.google/CJXLirYv6IFnBL1v2

है की वह विभिन्न प्रकार के शुल्क तथा शुल्क से जुड़े अन्य नीति-उपायों की समीक्षा करे, जिनका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी नई व्यापार नीति को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है|[24]

02 अप्रैल 2025 को उन्होंने लगभग सभी आयतों पर 10 प्रतिशत का सार्वभौमिक आधारभूत शुल्क घोषित किया, जबकि देश-विदेश के पारस्परिक शुल्क 09 अप्रैल से लागू होने थे| इस घोषणा के परिणामस्वरूप वैश्विक शेयर बाजार में भारी गिरावट आयी| परिणामस्वरूप, अमेरिकी सरकार को वार्ता के लिए समय देने हेतु नए शुल्को को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा| अंततः यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने अमेरिका के साथ बातचित की और नए शुल्क दरों पर समझौता किया| बांग्लादेश के संदर्भ में, ट्रम्प प्रशासन ने प्रारंभ में अमेरिका को होने वाले उसके निर्यात पर 35 प्रतिशत का ऊँचा पारस्परिक शुल्क लगा दिया था, जो पहले के लगभग 15 प्रतिशत के औसत से कहीं अधिक था और दक्षिण एशिया के निर्यातकों में सबसे ऊंची दरों में से एक था| इससे बांग्लादेश के परिधान(गार्मेंट्स) केंद्रों में गंभीर चिंताएं फैल गई, हजारों श्रमिकों को नौकरी जाने का दर सताने लगा, क्योंकि अमेरिकी खरीदारों ने 35 प्रतिशत शुल्क के कारण नए आर्डरों पर "देखो और इंतजार करो"(wait and see) की नीति अपना ली| हालांकि, वार्ता के माध्यम से बांग्लादेश 01 अगस्त से प्रभावी रूप से इस शुल्क को घटाकर 20 प्रतिशत कराने में सफल रहा|[25]

नई अमेरिकी प्रशासन इस अनुकूल परिस्थिति, जो संभवतः अल्पकालिक है का लाभ उठाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करना चाहता है, ताकि एक नया "पुराना विश्व व्यवस्था" स्थापित की जा सके, जो आने वाले दशकों तक अमेरिकी विश्व प्रभुत्व की कमजोर पड़ती नींव को फिर से मजबूत कर दे| यह महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी परियोजना कई पहलुओं को समाहित करती है, जो मिलकर एक सुसंगत और संयुक्त रणनीति बनाते हैं: 1. अमेरिका विनिर्माण उद्योग की वापसी की प्रक्रिया को गति देने के लिए शुल्क बढ़ाना, जो वर्तमान में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओ में बिखरा हुआ है, ताकि औद्योगिक पूंजी को संतुष्ट किया जा सके है| 2. कृषि-व्यवसाय और जीवाश्म ईंधन पूंजी को संतुष्ट करने के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियों को कमजोर करना या समाप्त करना| 3. और अंततः, निजी उच्च-प्रौद्योगिकी पूंजी को सार्वजनिक सैन्य- अंतरिक्ष परिसर में पूरी तरह एकीकृत करना, ताकि राजनीतिक प्रभुत्व और लाभ के लिए सूचना एवं संचार के वैश्विक नियंत्रण का एक मंच तैयार किया जा सके|[26]

[24] Lowell M., Heeren P., Angotti J., Rodriguez-johnson L., Lowell K., & Yeager E. (2026, January 27). *Trump 2.0 tariff tracker*. https://share.google/27ttgdWL8FXoCe2Qw

[25] https://www.biiss.org/event/bangladesh-us-tariff-deal-how-to-optimise-trade-benefit-1

[26] Ricci A. (2025). Global structure of dependency and socio-ecological crisis: Intersecting delinking and degrowth for an ecosocialist transition. *Capitalism Nature Socialism*, *36*(2), 1-21. https://doi.org/10.1080/10455752.2025.2485955

डोनाल्ड ट्रम्प की सत्ता मे वापसी दक्षिण एशिया के लिए, विशेष रूप से, बांग्लादेश के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों लेकर आई हैं| इस क्षेत्र को प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ जटिल संबंधों को संभालते हुए अपनी संप्रभुता बनाए रखने और लोकतान्त्रिक शासन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है| चूंकि ट्रम्प लोकतान्त्रिक मूल्यों की अपेक्षा रणनीतिक गठबंधनों को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए बांग्लादेशी नेतृत्व को ऐसी रणनीतिक कूटनीति अपनानी होगी जो बाहरी दबावों और घरेलू आकांक्षाओ के बीच संतुलन स्थापित कर सके| मुख्य प्रश्न यह है की क्या बांग्लादेश अमेरिका, भारत और चीन के परस्पर प्रतिस्पर्धा दबावों के बीच अपनी विदेश नीति को पुनर्परिभाषित कर सकता है? इसका उत्तर न केवल उसके निकट भविष्य की दिशा तय करेगा, बल्कि यह भी निर्धारित करेगा की महान शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से चिन्हित बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य में उसकी भूमिका कैसी होगी|[27]

ऐतिहासिक रूप से, बांग्लादेश ने चीन और भारत जैसे प्रभावशाली पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता है| किन्तु बदलता हुआ भू-राजनीतिक संदर्भ इन गठबंधनों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है| शेख हसीना द्वारा लगाए गए इस आरोप की सेंट मार्टिन द्वीप तक अमेरिका को पहुँच देने से इनकार करने के कारण उन्हें सत्ता से हटाया गया, के ठोस प्रमाण तो नहीं हैं, लेकिन यह आरोप म्यांमार के तट के निकट स्थित इस द्वीप के रणनीतिक महत्व को अवश्य रेखांकित करता हैं|[28]

ट्रम्प युग में अमेरिकी विदेश नीति का स्वरूप:

ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अमेरिकी विदेश नीति निरंतर एक सी नहीं रही है, बल्कि हाल के दशकों में इसमें कई बार परिवर्तन हुआ है, विशेषकर तब, जब सत्ता में डेमक्रैटिक तथा रिपब्लिकन राष्ट्रपति बारी-बारी से आए हैं| राष्ट्रपति प्रणाली और विदेश नीति निर्माण में कार्यपालिका की प्रमख भूमिका, राष्ट्रपति के बदलने के साथ-साथ विदेश नीति में परिवर्तन की संभावना को बढ़ा देती है| फिर भी, शीत-युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी विदेश नीति में कुछ बुनियादी सहमति बनी रही, जैसे बहुपक्षवाद का समर्थन| संयुक्त राज्य अमेरिका ने उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की बहुपक्षीय संस्थाओ को प्रोत्साहित किया और उन्हें शीत युद्धोत्तर व्यवस्था को संरचित करने का एक प्रभावी माध्यम मना|[29]

20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रम्प को संयुक्त राज्य अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, जिससे उनके दूसरे, गैर-एकतरफा कार्यकाल की शुरुआत हुई| उनके कार्यभार पर वापसी ने

[27] Aziz, M. A. (2025, December 8). *Between giants: Bangladesh's quest for sovereignty in trump's 2nd term*. Dailysabah.com. https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/between-giants-bangladeshs-quest-for-sovereignty-in-trumps-2nd-term

[28] Antora, A. R., & Muntasir T. (2025, November 2). *US foreign policy shifts and their impact on bangladesh and south asia's political landscape*. https://share.google/CJXLirYv6IFnBL1v2

[29] Saraiva, M. G. (2025, August 5). *Donald trump's foreign policy: A view from the global south*. GATE Center. https://gatecenter.org/en/donald-trumps-foreign-policy-a-view-from-the-global-south/

अमेरिकी विदेश नीति की दिशा को लेकर व्यापक चर्चाओं को जन्म दिया है, विशेष रूप से उनके "अमेरिकी फर्स्ट" नीति के संदर्भ में| यह नीति ढांचा, जो आर्थिक संरक्षणवाद, व्यापर प्रतिबंधों और पारंपरिक गठबंधनों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा पहचान जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की वैश्विक हस्तक्षेप रणनीति में एक मौलिक परिवर्तन का संकेत देता है|[30]

उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत एक दृढ़ अलगाववादी(isolationist) दृष्टिकोण के साथ की| उनकी "अमेरिकी फर्स्ट" नीति का वादा घरेलू मुद्दों पर ध्यान केन्द्रीत करने और विदेशी युद्धों से दूर रहने का था| ट्रम्प ने यूरोप की आलोचना करके और नाटो को छोड़ने की धमकी देकर अपने सहयोगी देशों को तुरंत ही विमुख कर दिया| उल्लेखनीय है की द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से नाटो अमेरिकी द्विदलीय विदेश नीति का एक केन्द्रीय स्तम्भ रहा है| पिछले आधे से अधिक शताब्दी तक नाटो ने यूरोप में रूसी आक्रामकता के विरुद्ध एक निवारक शक्ति(deterrent) के रूप में कार्य किया| इस निवारक व्यवस्था ने 1991 में सोविएत संघ के विघटन तक यूरोप में शांति बनाए रखी, जब शीत युध्द की समाप्ति पर पूरे विश्व ने राहत और उत्साह का अनुभव किया| व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन पर किए गए आक्रमण ने यह स्पष्ट कर दिया की रूसी साम्राज्य समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि केवल घायल था और प्रतिशोध की भवन से प्रेरित था| जहां पारंपरिक रिपब्लिकन नेता इस आक्रमण पर गंभीर चिंता और आक्रोश व्यक्त करते, वही ट्रम्प ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया| इसके अतिरिक्त, ट्रम्प स्वयं को जेलेन्सकी द्वारा ठगा हुआ महसूस करते थे, क्योंकि जेलेन्सकी ने जो-बाइडन के विरुद्ध उनका समर्थन नहीं किया था| दूसरी ओर, पुतिन ट्रम्प के साथ संबंध सुधारने और उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने बाइडन के विरुद्ध ट्रम्प का समर्थन भी किया था|[31]

विदेश नीति के क्षेत्र में ट्रम्प के दूसरे प्रशासन ने शुल्क को "गाजर और छड़ी"(carrot and stick) की रणनीति के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है| अधिकांश देशों के साथ ट्रम्प ने यह शर्त रखी है की अमेरिकी शुल्कों से बचने का एकमात्र तरीका संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश लाना है| वहीं कुछ अन्य देशों के साथ, विशेष रूप से अमेरिका के पड़ोसी देशों- कनाडा और मक्सिको के संदर्भ में, ट्रम्प ने शुल्क लगाने की धमकी दी है और उन्हें इससे बचने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिया है| इसके विपरीत, ट्रम्प ने लगातार कनाडा पर दबाव बनाने की नीति अपनाई है, ताकि भौगोलिक रूप से कनाडा के अमेरिका में विलय की संभावना को परखा जा सके| सिद्धांततः कनाडा का अमेरिका के "51 वें राज्य" के रूप में विलय एक अव्यावहारिक कल्पना प्रतीत होती है, किन्तु यह ट्रम्प प्रशासन की ओर से कनाडा के साथ

[30] Antora, A. R., & Muntasir T. (2025, November 2). *US foreign policy shifts and their impact on bangladesh and south asia's political landscape*. https://share.google/CJXLirYv6IFnBL1v2
[31] Reese T. (2026, January 7). *Trump's foreign policy is a disaster for america and the world*. Ncronline.org. https://share.google/fQFB8biCRAN9IIwqY

रचनात्मक संवाद करने की राजनीतिक अनिच्छा को दर्शाता है और ओटावा पर शुल्क लगाए जाने की संभावना को और प्रबल करता है|[32]

भारत ने वर्ष 2025 में इस आशा के साथ प्रवेश किया था की डोनाल्ड ट्रम्प का दूसरा राष्ट्रपति कार्यकाल दोनों देशों के संबंधों के लिए सकारात्मक सिद्ध होगा| भारत में जनमत भी व्हाइट हाउस में ट्रम्प की वापसी को लेकर अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल था| किन्तु ट्रम्प ने इस धारणा को बदल दिया| कार्यक्षेत्र संभालने के बाद से ट्रम्प ने शुल्कों में वृद्धि की है, H-1B वीजा पर प्रतिबंध कड़े किए है| हालिया घटनाक्रम भारत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक रहा है, ट्रम्प द्वारा एक ऐसे विधेयक का समर्थन, जिसमें अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 500 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव है| इससे भारत को 500 शुल्क लगाने का झटका लगा है|[33]

व्हाइट हाउस में वापसी के बाद अपने पहले ही वर्ष में ट्रम्प ने यमन में उग्रवादियों पर और ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बमबारी करवाई, गाजा में एक अल्प युद्धविराम की मध्यस्थता की, यूरोपीय नेताओं को अपने रक्षा व्यय बढ़ाने के लिए बाध्य किया, चीन से वाणिज्यिक और रणनीतिक प्रतिबद्धताएं प्राप्त की, डेनमार्क से ग्रीनलैंड सौंपने की बात की, अमेरिका के लगभग सभी प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर शुल्क लगाने की धमकी दी| उन्होंने अर्जेन्टीना के राष्ट्रपति को आर्थिक संकट से उबारने के लिए अरबों डॉलर की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई, मादक पदार्थों की तस्करी के अपराध में दोषी ठहराए गए होण्डुरास के एक पूर्व राष्ट्रपति को रिहा करवाया, तथा कैरेबियन और प्रशांत महासागर में कथित मादक पदार्थों से भरी नौकाओं पर ऐसे हमलों को मंजूरी दी जिनमें 95 से अधिक लोगों की मौत हो गई- जिससे युद्ध अपराधों के आरोप भी लगे|[34] ट्रम्प ने इसके अतिरिक्त जिसे वह **"डोनरों सिद्धांत"(donroe doctrine)** कहते है, उसका भी प्रतिपादन किया है, जो मुनरो सिद्धांत पर आधारित एक शब्द खेल है और पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका की भूमिका की एक नई कल्पना प्रस्तुत करता है| इस दृष्टिकोण में आए परिवर्तन को वेनेजुएला में किए गए एक जमीनी अभियान द्वारा और अधिक रेखांकित किया गया, जिसका उद्देश्य तात्कालिन राष्ट्रपति निकोलस मादूरों को पकड़कर अमेरिका लाना था, ताकि उन पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कार्टेलों को समर्थन देने के कथित आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जा सके|

[32] Pant, H. V., & Mishra V. (2025, February 1). *Trump's domestic ambitions and the global order*. https://share.google/mea6eWVVdZq7krZHc
[33] Shankar K. (2026, January 12). *Erratic, expansionary, dominance: Trump's first year of second term*. Siasat.com. https://share.google/9K4S9oZN1cJEkI81i
[34] Bennett B., & Popli N. (2026, January 15). How trump's foreign policy gambits are reshaping the world. *TIME*. https://time.com/collections/davos-2026/7345543/trump-foreign-policy-second-term/

वास्तव में, ट्रम्प ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के **"मैडमैन सिद्धांत"** को खुले तौर पर अपनाया है, जिसका प्रयोग कभी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उत्तरी वियतनाम और सोविएत संघ के साथ अपने संबंधों में किया था| इस सिद्धांत के अनुसार, जिस नेता को तर्कहीन और अप्रत्याशित माना जाता हो, उसके साथ संबंधों का प्रबंधन करते समय उसका सीधे सामना करना अत्यधिक जोखिमपूर्ण होता है; ऐसे में उसे कुछ रियायतें देना अधिक विवेकपूर्ण मार्ग समझा जाता है| समस्या यह है की यह सिद्धांत व्यवहार में उतनी बार सफल नहीं होता जितना की सैद्धांतिक रूप में प्रतीत होता है| अप्रत्याशितता कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में उपयोगी हो सकती है, किन्तु सम्पूर्ण विदेश नीति की आधारशीला के रूप में इसे अपनाना गंभीर कमजोरियों से ग्रस्त है|

ट्रम्प युग में अमेरिका-बांग्लादेश संबंध:

अप्रैल 1972 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद से दोनों देशों ने सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं| समय के साथ इन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर मजबूती आई है, जिसका चरम बिन्दु वर्ष 2022 में राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती का उत्सव रहा| वर्तमान में बांग्लादेश संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने ऊर्जा क्षेत्र का सबसे बड़ा साझेदार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत, तथा अपने रेडिमेंट गार्मेंट्स के लिए सबसे बड़ा बाजार गंतव्य मानता है|[35]

लॉर्ड्स पामर्स्टन के प्रसिद्ध कथन के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न तो कोई स्थायी मित्र है और न ही कोई स्थायी शत्रु| केवल राष्ट्रीय हित ही स्थायी होते हैं और उन्हें दृढ़ता से आगे बढ़ाया जाता है| तथापि, बांग्लादेश-अमेरिका संबंधों के संदर्भ में दीर्घकालिक साझेदारी एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है| वैश्विक राजनीति में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक और सैन्य शक्ति की दृष्टि से विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना हुआ है| बांग्लादेश के लिए अमेरिका उसके सबसे बड़े रणनीतिक, व्यापारिक और विकास साझेदारों में से एक है| दूसरी ओर, हाल के वर्षों में अमेरिका ने बांग्लादेश में उसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण गहरी रुचि दिखाई है|[36] बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक प्रमुख तटीय देश है| यह हिन्द महासागर तक पहुँच प्रदान करता है और दक्षिण एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण भौगोलिक सेतु का कार्य करता है| अपनी इसी रणनीतिक स्थिति के कारण बांग्लादेश अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्यों में विशेष महत्व रखता है और इसलिए यह महाशक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण रुचि का क्षेत्र बन गया है| क्षेत्रीय मुद्दे अमेरिका-बांग्लादेश संबंधों को गहराई से प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से ऐसे समय में जब चीन का प्रभाव बढ़

[35] Mahmud, K. U. (2024). How did bangladesh and the US maintain their bilateral relationship in 2023? *The Center for Bangladesh and Global Affairs*, 1-6. https://doi.org/10.2139/ssrn.5411664
[36] Hassan, M. S., & Mostaque L. Y. (2024). Bangladesh-US relations: Managing the asymmetry in the changing global scenarios. *Journal of Bangladesh and Global Affairs*, *03*. https://doi.org/10.55875/JBGA. V3N1-2A3

रहा है और वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव आ रहा है| भारत और म्यांमार के बीच स्थित होने के कारण बांग्लादेश एक व्यावहारिक और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है| इसके पड़ोसी देशों, खासकर भारत और म्यांमार के साथ इसके संबंध भी अमेरिका के साथ इसके रिश्तों को प्रभावित करते हैं| यह स्थिति दर्शाती है की दक्षिण एशिया और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय गतिशीलताएं किस प्रकार परस्पर जुड़ी हुई हैं और किस तरह वे द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संबंधों को आकार देती हैं|[37] हालिया मीडिया रेपोर्टों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका क्वाड के "पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्ट्नर्शिप" के तहत बांग्लादेश में एक बंदरगाह विकसित करने की योजना बना रहा है| यह पहल औपचारिक रूप से आक्टूबर 2025 से शुरू की जानी थी|[38]

अमेरिकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ उसके संबंधों में आर्थिक हित सबसे प्रमुख और निर्णायक कारक के रूप में उभरते हैं| इसका प्रमाण 1976 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विदेश नीति के उद्देश्यों की सूचि से मिलता है| उल्लेखनीय है की उस सूचि में बांग्लादेश से संबंधित अमेरिका के पाँच में से चार विदेश नीति उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी आर्थिक हितों से जुड़े हुए थे| यद्यपि ये उद्देश्य 1976 में निर्धारित किए गए थे, फिर भी आज तक उनकी मूल दिशा में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है| 2010 की कॉंग्रेसनल रिपोर्ट ने भी इसी बात की पुष्टि की, जिसमें यह रेखांकित किया गया की बांग्लादेश में अमेरिकी हितों में विकास को बढ़ावा देना, व्यापार और ऊर्जा सहयोग, लोकतंत्र का समर्थन, उग्र इस्लामी आतंकवाद का मुकाबला करना तथा शांति अभियानों में सहयोग शामिल है| राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस बात पर जोर दिया था की बांग्लादेश का बाजार अमेरिकी जनता की समृद्धि के लिए आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है| अमेरिकी कंपनियां बांग्लादेश की संभावनाओ को पहचानती हैं और वहाँ व्यापार करने के लिए उत्सुक हैं| वास्तव में, यह तर्क दिया जा सकता है की व्यापार और निवेश बांग्लादेश में अमेरिका के दो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक हित हैं|[39]

बाइडेन प्रशासन की उस नीति के विपरीत, जिसमें अमेरिकी विदेश नीति में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को नैतिक और वैचारिक रूप से विशेष महत्व दिया गया, ट्रम्प का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक और ट्रांस-सेक्शनल आधारित रहा है| बाइडेन प्रशासन ने अगस्त में हुए जनविद्रोह के बाद गठित मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का सक्रिय रूप से समर्थन किया है| इसके विपरीत, ट्रम्प द्वारा इस अंतरिम सरकार के प्रति इसी स्तर का उत्साह दिखाए जाने की संभावना कम

[37] Mohsin, S. S., Ibnat A., & Jahan S. (2025). The trajectory of US-Bangladesh relations under the second trump administration. *ISDA*, *35*, 27-59. https://doi.org/0971-2550

[38] Bose S. (2025, October 3). *US-Bangladesh ties: Ports, power, and partnerships*. https://www.orfonline.org/expert-speak/us-bangladesh-ties-ports-power-and-partnerships

[39] Islam, D. M. S. (2023, June 7). Why does bangladesh matter to the united states? *THE FINANCIAL EXPRESS*. https://thefinancialexpress.com.bd/views/views/why-does-bangladesh-matter-to-the-united-states

है| वास्तव में, कई विश्लेषकों का तर्क है की यूनुस की प्रमुख डेमक्रैट नेताओं, विशेषकर क्लिंटन परिवार से निकटता के कारण ट्रम्प इस अंतरिम सरकार को नकारात्मक दृष्टि से देख सकते हैं| 2016 में हिलेरी क्लिंटन पर ट्रम्प की चुनावी जीत के तुरंत बाद, पेरिस में एक सम्मेलन में बोलते हुए यूनुस ने इस परिणाम की तुलना "सूर्यग्रहण" से की थी और कहाँ था की "ट्रम्प की जीत ने हमें इतना झकझोर दिया की मैं मुश्किल से बोल पा रहा था| मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई थी|" इसके अतिरिक्त, 31 अक्टूबर को प्रकाशित एक ट्वीट में ट्रम्प ने बांग्लादेश में हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ तथाकथित "बर्बर हिंसा" की नींदा की और टिप्पणी की कि उनके कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता| इसे अमेरिकी चुनावी राजनीति के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि रिपब्लिकन और डेमक्रैट दोनों ही भारतीय-अमेरिकी और हिन्दू-अमेरिकी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे| हालांकि कुछ विश्लेषकों ने इस पोस्ट की व्याख्या इस संकेत के रूप में की है की ट्रम्प प्रशासन के तहत वाशिंगटन एक बार फिर बांग्लादेश को भारत के दृष्टिकोण से देखने की आवृती अपना सकता है|[40]

ट्रम्प के कार्यकाल के दौरान अमेरिका और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा सहयोग में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ| आतंकवाद-विरोधी सहयोग एक साझा प्राथमिकता के रूप में उभरा, जिसके तहत अमेरिका ने बांग्लादेश की सीमाओं के भीतर हिंसक उग्रवाद से निपटने के लिए समर्थन प्रदान किया| संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों और सैन्य सहायता ने दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत किया, जो क्षेत्रीय स्थिरीता में उनकी पारस्परिक रुचि को दर्शाता है| हालांकि, इन प्रयासों पर कभी-कभी बांग्लादेशी सुरक्षा बलों द्वारा किए गए मानवाधिकार उलँघनों को लेकर अमेरिकी चिंताओं की छाया पड़ती रही है|[41]

ट्रम्प का चुनाव अभियान प्रवासन-विरोधी बयानबाजी से भरा हुआ था, जिसमें अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की बात शामिल थी| प्रॉथोंम आलो(prothom alo) की 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने उस वर्ष 11 बांग्लादेशी प्रवासियों को अमेरिका से निर्वासित किया था| यह घटनाक्रम दर्शाता है की ट्रम्प की सख्त आप्रवासन नीतियाँ केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका प्रभाव बांग्लादेश जैसे देशों और उनके प्रवासी समुदायों पर भी पड़ सकता है|[42]

ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई, और अमेरिकी कॉम्पनियों ने बांग्लादेश में भी अपने निवेश को काफी बढ़ाया| व्यापार और आर्थिक व्यवहारिकता पर ट्रम्प के जोर के चलते बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरा|

[40] Rahman, M. H. (2024, November 14). *What a second trump presidency means for bangladesh*. https://thediplomat.com/2024/11/what-a-second-trump-presidency-means-for-bangladesh/
[41] Mohsin S. (2025, January 24). Trump policy shifts: Bangladesh treads tightropes. *NEWAGE*. https://www.newagebd.net/print/post/256139
[42] Hossain M. (2024, October 16). Will a trump presidency impact US-Bangladesh relations?. *The Business Standard*. https://share.google/wk5wvf5BChv3M3NuX

दूसरे कार्यकाल में भी व्यापार और निवेश पर यह जोर फिर से देखने को मिल सकता है| हालांकि, बांग्लादेश के सामने मौजूद वर्तमान आर्थिक चुनौतियाँ इस प्रक्रिया को जटिल बना सकती हैं|[43]

बांग्लादेश में राजनीतिक एवं रणनीतिक संकट:

बांग्लादेश की सबसे लंबे समय से सत्ता में रहने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्होंने 20 से अधिक वर्षों तक कठोर शासन किया, ने 5 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया और भारत चली गई| उनका यह नाटकीय प्रस्थान एक महीने लंबे छात्र नेतृत्व वाले विरोध आंदोलन के बाद हुआ, जिसकी शुरुआत सरकारी नौकरियों मे कोटा प्रणाली में सुधार की मांग से हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे यह आंदोलन शेख हसीना के इस्तीफे और लोकतान्त्रिक सुधारों की मांग करते हुए एक व्यापक जन विद्रोह में बदल गया| 1 जुलाई को विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है| अकेले 4 अगस्त को ही लगभग 100 लोगों की जान गई, जब हसीना सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कठोर दमन किया, जिसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ, देखते ही गोली मारने के आदेश, कर्फ्यू लागू करना तथा इंटरनेट और संचार सेवाओं को बंद करना शामिल करना था| जब प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी कर्फ्यू को चुनौती देते हुए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास की ओर मार्च किया, तो रेपोर्टों के अनुसार देश की सुरक्षा अजेंसियों ने शेख हसीना को 45 मिनट का अंतिम चेतावनी दिया की वे इस्तीफा दे और देश छोड़ दे, इससे पहले की आक्रोशित भीड़ उनके घर पर धावा बोल दे|[44]

निर्णायक मोड़ जून 2024 में आया, जब बांग्लादेश की उच्च न्यायालय ने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण फिर से बहाल कर दिया| स्नातकों में बढ़ती बेरोजगारी के कारण सरकारी नौकरियों की मांग पहले से ही बहुत अधिक थी| ऐसे में छात्रों ने इस कोटा प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए| उनका यह भी मानना था की यह व्यवस्था शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के समर्थकों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है| अंततः जुलाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया|[45]

शेख हसीना सरकार के पतन के बाद शीघ्र ही एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता और व्यापक रूप से सम्मानित मुहम्मद यूनुस ने मुख्य सलाहकार के रूप में

[43] Islam T. (n.d.). *Trump's critique of bangladesh and its implications for US relations*. Thearabianpost.com. https://thearabianpost.com/trumps-critique-of-bangladesh-and-its-implications-for-us-relations/?srsltid=AfmBOorx6CS18RosiwvVKTeaCvdTQ-pRhzd4H0k4sBKPvAQfIi2tn7ai

[44] Datta S. (2024, august,7). *What are the ramifications of bangladesh's political turmoil for india, broader region?* Asia Pacific Foundation of Canada. https://www.asiapacific.ca/publication/explainer-bangladeshs-popular-uprising-creates-political-uncertainty

[45] Chaudhari, R. R., & Solanki V. (2024, August 20). *Bangladesh: Domestic turmoil and regional insecurity*. Iiss.org. https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2024/08/bangladesh-domestic-turmoil-and-regional-insecurity/

संभाला| यह सरकार एक विविध समूह से मिलकर बनी है, जिसमें आंदोलन की अग्रिम पद्दती में छात्र नेता, नागरिक समाज के प्रमुख व्यक्ति, अनुभवी पूर्व नौकरशाही तथा उच्च-पदस्थ सैन्य अधिकारी शामिल हैं| अंतरिम प्रशासन को एक स्पष्ट जनादेश सौंपा गया है- राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की निगरानी करना, जिनमें चुनावी प्रणाली, पुलिस बल और संविधान शामिल हैं, तथा इसके बाद नए राष्ट्रीय चुनाव कराना|[46]

बांग्लादेश के राजनीतिक संक्रमण ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक ध्यान आकर्षित किया है, विशेष रूप से अमेरिका और भारत की ओर से, जो क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं| यूनुस प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है की वह इन सहयोगी देशों के साथ आई.एम.एफ. और विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय संस्थाओ से आर्थिक समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेगा, हालांकि नीतिगत स्वायतता बनाए रखना उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा| इस क्षेत्र में चीन भी एक अहम भूमिका निभाता है, जिससे वैश्विक साझेदारियों और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए रणनीतिक कूटनीति अनिवार्य हो जाती हैं| बांग्लादेश के प्रमुख निर्यात बाजारों में से एक जर्मनी अपने विकास सहयोग को जलवायु, सुशासन और सतत आपूर्ति शृंखलाओं जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित करता है| चूंकि जर्मनी को होने वाले बांग्लादेशी निर्यात का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा वस्त्र (टेक्सटाइल) क्षेत्र से आता है, यह साझेदारी न केवल दोनों देशों की आर्थिक वृद्धि को समर्थन देती है, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता को भी बढ़ावा देती है|[47]

“अगस्त विद्रोह” के बाद से 140 से अधिक कारखाने बंद हो चुके हैं या नष्ट हो गए हैं| कुछ अनुमानों के अनुसार 20 लाख से अधिक श्रमिकों की नौकारियां चली गई हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं|[48] 2023 में बांग्लादेश ने एक स्वतंत्र, खुला, शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समावेशी हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के समर्थन की घोषणा की और यह भी आग्रह किया की हिन्द-प्रशांत सुरक्षा साझेदारों के साथ सहयोग में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं जैसे अधिक तात्कालिक और गंभीर गैर-पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों को शामिल किया जाए| आंतरिक कमजोरियाँ और राजनीतिक अस्थिरता मिलकर राज्य को कमजोर बना सकती हैं| हालांकि, यही स्थिति सुधारों के अवसर भी पैदा करती है| साथ ही, सुधारों की यह आवश्यकता नए साझेदारों और प्रतिस्पर्धी दाताओं जैसे- चीन को भी आकर्षित कर सकती है, जिससे इस छोटे हिन्द-प्रशांत देश में उनके निवेश का दायरा बढ़ सकता है|[49]

[46] Mukherjee A. (2025). Bangladesh crisis and challenges for india. *Ssrn*. https://doi.org/10.2139/ssrn.5284473
[47] Koshti V. (2024, August 16). *Crisis and reform in bangladesh*. Rosalux.de. https://www.rosalux.de/en/news/id/52785/crisis-and-reform-in-bangladesh
[48] Chaudhury, J. R. (2025, June 12). *Bangladesh crisis: Rising tensions, fragile governance, regional fallout*. Thesecretariat.in. https://thesecretariat.in/article/bangladesh-crisis-rising-tensions-fragile-governance-regional-fallout
[49] Rasheed, D. A., & Banarjee S. (2024, August 22). *Bangladesh's political change: Implications for the indo-pacific*. https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/bangladeshs-political-change-implications-for-the-indo-pacific/

"डीप-स्टेट" के दृष्टिकोण से देखने पर यह स्पष्ट होता है की बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक और नौकरशाही गतिशीलताएं उसकी विदेश नीति के झुकाव और गठबंधनों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं| सैन्य अभिजात वर्ग- जिन्हें अमेरिका, चीन, भारत और तुर्की में व्यापक प्रशिक्षण मिला है- के भू-राजनीतिक झुकाव अलग-अलग हैं| वहीं सिविल सेवा(नौकरशाही) के नेटवर्क अक्सर पश्चिमी कूटनीतिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ जुड़े रहते हैं, जिससे उनकी नीति-संबंधी सोच अमेरिकी शासन और प्रशासनिक ढांचों के अनुरूप ढलती जाति है| इसी समय, राजनीतिक और व्यावसायिक अभिजात वर्ग के चीनी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के साथ लाभकारी संबंध बने हुए हैं| ये परस्पर जुड़ी हुई लेकिन भिन्न-भिन्न नेटवर्क संरचनाएं बांग्लादेश की विदेश नीति व्यवस्था में संरचनात्मक तनाव पैदा करती हैं, जिससे नीति-निर्माण में सुसंगति बनाए रखना लगातार कठिन होता जा रहा है| अमेरिका यह तर्क प्रस्तुत करते हुए सॉफ्ट पावर विकसित करने का प्रयास करता है की बांग्लादेश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता लोकतान्त्रिक मानदंडों के पालन पर निर्भर करती है| इसके विपरीत, चीन ऐसा विमर्श आगे बढ़ाता है जिसमें आर्थिक विकास को राष्ट्रीय सशक्तिकरण का मुख्य मार्ग बताया जाता है, जो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए|[50]

विश्लेषणात्मक चर्चा एवं निष्कर्ष:

वर्तमान ट्रम्प प्रशासन के दौरान अमेरिका के विदेश-नीति में आए परिवर्तन का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता हैं की ट्रम्प की विदेश नीति संरक्षणवाद और एकतरफा निर्णय पर आधारित है, क्योंकि ट्रम्प के सरकार में आते ही बहुपक्षीय संस्थाओ से विच्छेद कर लिया गया| हाल ही में प्रस्तुत अलजजीरा समचार के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन का कहना है की अमेरिका 66 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओ से अलग होने जा रहा है, जिसमें 31 संयुक्त राष्ट्र के अंदर निहित हैं तथा 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठन है|[51] ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति अपनाई है, जो राष्ट्र की संप्रभुता, घरेलू नीतियों को प्राथमिकता देती हैं|

वर्तमान में ट्रम्प प्रशासन के अंतर्गत अमेरिका का दृष्टिकोण उदारवाद से हटकर यथार्थयादी हो गया है| जैसे- एकतरफा शुल्क का लगाया जाना अमेरिका के प्रभुत्व को दर्शाता हैं, जो राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखता हैं, वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप तथा ग्रीनलैंड पर अधिकार जमाने की कोशिश, अमेरिका क्षेत्रीय

[50] Ahmed M. (2025). Bangladesh at the crossroads of US-china strategic rivalry: A deep state and hegemonic influence perspective. *Ssrn*. https://doi.org/10.2139/ssrn.5815904
[51] (2026, January 8). Which are the 66 global organisations the US in leaving under trump? *ALJAZEERA*. https://www.aljazeera.com/news/2026/1/8/which-are-the-66-global-organisations-the-us-is-leaving-under-trump

शक्ति संतुलन को फिर से परिभाषित करने और प्रतिद्वंदी शक्तियों के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहा है|

'दिस वीक इन एशिया' में प्रकाशित आलेख के अनुसार, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी(USAID) से सहायता प्राप्त करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है, लंबे समय से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, शिक्षा पहलों को आगे बढ़ाने और आर्थिक अस्थिरीता से निपटने के लिए इस सहायता पर निर्भर रहा हैं| लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा सभी सहायता कार्यक्रमों की 90 दिनों तक समीक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की, वे अमेरिकी विदेश नीति के अनुरूप हों|[52] इससे स्पष्ट होता हैं की अमेरिका का घरेलू हीत वैश्विक हित के अपेक्षा प्राथमिक हैं और बांग्लादेश की कहीं न कहीं अमेरिका पर निर्भरता भी बनी हुई हैं, क्योंकि USAID की सहायता से बांग्लादेश को स्वास्थय, कृषि, शिक्षा और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण लाभ पहुंचता है| यदि अमेरिका द्वारा इस सहायता को समय-समय पर बंद कर दिया जाएगा, तो बांग्लादेश को काफी संकट का सामना करना पड़ सकता है|

बांग्लादेश के साथ ट्रम्प प्रशासन का संबंध आर्थिक, सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोगात्मक रहा हैं, लेकिन दोनों देशों के मध्य आर्थिक विषमता के कारण बांग्लादेश की अमेरिका पर निर्भरता बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश रेडिमेंट गार्मेंट्स का प्रमुख निर्यातक देश हैं, और अमेरिका बांग्लादेश के लिए एक बड़ी बाजार हैं| हाल ही में, अमेरिका द्वारा बांग्लादेश के निर्यात पर 37 प्रतिशत शुल्क आरोपित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन आपसी वार्ता के माध्यम से इसे घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता हैं की ट्रम्प का दृष्टिकोण बांग्लादेश को लेकर सहयोगात्मक भी हैं|

बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी में स्थित देश हैं, जो चीन और अमेरिका के लिए प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र हैं| दोनों ही देश हिन्द- प्रशांत क्षेत्र में अपने शक्तियों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं| द मोरुङएक्स्प्रेस समाचार के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन और व्यापक इंडो-पेसिफिक क्षेत्र को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के केंद्र में रखा है| यह रणनीतिक प्राथमिकता इस बात को दर्शाती है की, वाशिंगटन मानता है की हिन्द-प्रशांत पर प्रभाव न केवल वैश्विक आर्थिक शक्ति की दिशा तय करेगा, बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका की सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि को भी प्रभावित करेगा| युद्ध विभाग द्वारा जारी 2026 की रक्षा रणनीति रिपोर्ट के अनुसार, निकट भविष्य में हिन्द-प्रशांत वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधे से अधिक हिस्सा बनने जा रहा है| इस कारण, इस क्षेत्र तक अमेरिका की सतत पहुँच को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित के रूप में देखा गया है| रणनीति यह भी चेतावनी देती हैं की यदि चीन या कोई अन्य बड़ी शक्ति

[52]Mukherji B. (2025). *US aid freeze threatens bangladesh's fragile economy and political stability*. THIS WEEK IN ASIA. https://amp.scmp.com/week-asia/politics/article/3296616/us-aid-freeze-threatens-bangladeshs-fragile-economy-and-political-stability

हिन्द-प्रशांत पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, तो वह अमेरिका की पहुंच को "विश्व की आर्थिक शक्ति के केंद्र" तक प्रभावी रूप से रोक सकती है|[53] इससे स्पष्ट हैं की अमेरिका को हिन्द-प्रशांत क्षेत्र पर प्रभाव बनाए रखने के लिए बांग्लादेश का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि चीन द्वारा अपने "डेप्ट ट्रैप" नीति के माध्यम से बांग्लादेश पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है और बांग्लादेश चीन के "बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव(BRI) का आधिकारिक तौर पर हिस्सा भी हैं|

बांग्लादेश में हुई राजनीति संकट के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को पद से इस्तीफा देना पड़ा| शेख हसीना के द्वारा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन पर आरोप लगाया गया की बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का कारण, अमेरिका है, क्योंकि उन्होंने मार्टिन द्वीप को अमेरिका को देने से मना कर दिया था और वो देश की संप्रभुता को दाव पर लगाकर चुनाव नहीं जितना चाहती, लेकिन अमेरिका द्वारा इन आरोपों को खारिज कर दिया गया|

वर्तमान बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने, 2016 के अमेरिकी चुनाव प्रचार में हेनरी क्लिंटन का समर्थन किया था और डोनाल्ड ट्रम्प के चुनाव जीत को "सूर्य ग्रहण" और "काले दिन" कहा था, जिससे ट्रम्प प्रशासन और यूनुस के बीच तनावपूर्ण संबंध थे, लेकिन बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा के बाद मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया गया, जिसका डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरी तरह सहयोग किया और 2024 के अमेरिकी चुनाव मे डोनाल्ड ट्रम्प की जीत को यूनुस ने भी पूरा सहयोग किया, जिससे स्पष्ट होता हैं की दोनों देश पारस्परिक द्विपक्षीय संबंध को बनाए रखना चाहते हैं तथा बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक परिवेश का दोनों देशों की संबंधों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर रही हैं|

इस शोध के विश्लेषण से स्पष्ट हैं की वर्तमान ट्रम्प 2.0 प्रशासन के तहत अमेरिका की 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति अपने घरेलू नीतियों को प्राथमिकता दिया जा रहा हैं, जिसके लिए ट्रम्प द्वारा शुल्कों का आरोपण और बहुपक्षीय संस्थाओ से दूरी बनाना आदि का सहारा लिया जा रहा है| इसके बावजूद भी बांग्लादेश के साथ अमेरिका का संबंध सहयोगात्मक हैं, क्योंकि अमेरिका के यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो, अमेरिका का हिन्द-प्रशांत क्षेत्र पर प्रभाव बनाए रखना उसके हितों की पुष्टि करता हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बांग्लादेश के साथ सहयोगात्मक संबंध को बनाए रखना अमेरिका के लिए आवश्यक है तथा इस सहयोगात्मक संबंध से चीन का हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलेगी| बांग्लादेश-अमेरिका का संबंध आर्थिक विषमता तथा शक्ति विषमता पर आधारित हैं, जिससे बांग्लादेश की निर्भरता अमेरिका के ऊपर ज्यादा हैं| अमेरिका के लिए इस निर्भरता को बनाए रखना उसके हितों के अनुरूप हैं| वर्तमान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस पूर्व में ट्रम्प के

[53] (2026, January 25). US defence strategy puts china, indo-pacific first. THE MORUNGEXPRESS. https://morungexpress.com/us-defence-strategy-puts-china-indo-pacific-first

आलोचक होने के बावजूद भी, ट्रम्प प्रशासन में बांग्लादेश-अमेरिका का संबंध सहयोगात्मक हैं तथा वर्तमान में बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक-रणनीतिक संकट के प्रति ट्रम्प की चिंता हिन्दुओं और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा को लेकर भी हैं, और यह भी चिंता व्यक्त की हैं की बांग्लादेश में चुनाव को निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराया जाए|

शोध संदर्भ:

1. Islam, M. S. (2023, June 7). Why does bangladesh matter to the united states? *THE FINANCIAL EXPRESS*. https://thefinancialexpress.com.bd/views/views/why-does-bangladesh-matter-to-the-united-states
2. Hasan, R. A. (2025, January 21). Trump's america first doctrine and its ripple effects on bangladesh. *The Daily Star*. https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/trumps-america-first-doctrine-and-its-ripple-effects-bangladesh-3804376
3. Jasmin, I. A., & Hosen I. (2025). Trump 2.0: Redefining america's role in the global order. *Discover Global Society*. https://doi.org/10.1007/s44282-025-00281-7
4. Mahmud, K. U. (2024). Will trump 2.0 change US policy towards bangladesh? *The Business, Dhaka, Bangladesh. SSRN*, 1-4. https://doi.org/10.2139/ssrn.5413874
5. Mohsin, S. S., Ibnat A., & Jahan S. (2025). The trajectory of US-Bangladesh relations under the second trump administration. *ISDA*, *35*, 27-59. https://doi.org/0971-2550
6. Sakhuja, D. V. (2025). *Bangladesh in the crosshair of big powers contestation*. REVA University. www.rewa.edu.in
7. Ahmed M. (2025). Bangladesh at the crossroads of US-China strategic rivalry: A deep state and hegemonic influence perspective. *SSRN*. https://doi.org/10.2139/ssrn.5815904
8. Alden, C. & Aran, A. (2011). Foreign policy analysis – an overview. In: Foreign Policy Analysis: New Approaches. (pp. 1-14). Routledge. ISBN 9780203640999)
9. Hong, D. L. T. (2022). Foreign policy analysis - an approach from policy theory. *Migration Letters*, *19*, 1656-1665.
10. Saraiva, M. G. (2025, May 8). *Donald trump's foreign policy: A view from the global south*. GATE Center. https://gatecenter.org/en/donald-trumps-foreign-policy-a-view-from-the-global-south/
11. https://share.google/7mtTk4WAH24Ca6thD
12. Reiss, A. M. (2026, January 20). *Trump's foreign policy after year one: A look back, a look ahead*. Rusi.org. https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/trumps-foreign-policy-after-year-one-look-back-look-ahead
13. Obaidullah M. (2024, December 30). *Trump 2.0 and bangladesh 2.0: Redefining dynamics in a new era of bilateral relations- analysis*. Eurasiareview.com. https://share.google/FA7ks6v3G0MkIqEPv
14. Asuquo, E. E., Deborah A., & Jason emeka U. (2024). Dependency theory and development policy in a 21st century context. *Journal of Political Discourse*, (4). https://www.researchgate.net/publication/388106151_DEPENDENCY_THEORY_AND_DEVELOPMENT_POLICY_IN_A_21ST_CENTURY_CONTEXT
15. Kvangraven, I. H. (2020). Beyond the stereotype: Restating the relevance of the dependency research programme. *Development and Change*, *52*(1), 76-112. https://doi.org/10.1111/dech.12593

16. Oyetunde, O. S. (2022, August 17). *Is dependency theory relevant in the twenty-first century?* E-Ir.Info. https://share.google/SUAv3NYCFqQMYPZNt
17. Ahmed Z., Habib, M. A., & Khan , S. R., opee (2023). The economic contributions of usa to bangladesh: An evaluation of bilateral relations over 50 years. *Bangladesh Journal of Integrated Thoughts*. https://doi.org/10.52805/bjit.v19i1.295
18. Banerjee, D. S. (2024, September 10). *The shift in us-bangladesh relations*. Icwa.in. https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=11768&lid=7167
19. Bose S. (2023, May 29). *A hitch in bangladesh-US relations?* https://www.orfonline.org/expert-speak/a-hitch-in-bangladesh-us-relations
20. Antora, A. R., & Muntasir T. (2025, November 2). *US foreign policy shifts and their impact on bangladesh and south asia's political landscape*. https://share.google/CJXLirYv6IFnBL1v2
21. Lowell M., Heeren P., Angotti J., Rodriguez-johnson L., Lowell K., & Yeager E. (2026, January 27). *Trump 2.0 tariff tracker*. https://share.google/27ttgdWL8FXoCe2Qw
22. https://www.biiss.org/event/bangladesh-us-tariff-deal-how-to-optimise-trade-benefit-1
23. Ricci A. (2025). Global structure of dependency and socio-ecological crisis: Intersecting delinking and degrowth for an ecosocialist transition. *Capitalism Nature Socialism*, *36*(2), 1-21. https://doi.org/10.1080/10455752.2025.2485955
24. Aziz, M. A. (2025, December 8). *Between giants: Bangladesh's quest for sovereignty in trump's 2nd term*. Dailysabah.com. https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/between-giants-bangladeshs-quest-for-sovereignty-in-trumps-2nd-term
25. Reese T. (2026, January 7). *Trump's foreign policy is a disaster for america and the world*. Ncronline.org. https://share.google/fQFB8biCRAN9IIwqY
26. Pant, H. V., & Mishra V. (2025, February 1). *Trump's domestic ambitions and the global order*. https://share.google/mea6eWVVdZq7krZHc
27. Shankar K. (2026, January 12). *Erratic, expansionary, dominance: Trump's first year of second term*. Siasat.com. https://share.google/9K4S9oZN1cJEkI81i
28. Bennett B., & Popli N. (2026, January 15). How trump's foreign policy gambits are reshaping the world. *TIME*. https://time.com/collections/davos-2026/7345543/trump-foreign-policy-second-term/
29. Mahmud, K. U. (2024). How did bangladesh and the US maintain their bilateral relationship in 2023? *The Center for Bangladesh and Global Affairs*, 1-6. https://doi.org/10.2139/ssrn.5411664
30. Hassan, M. S., & Mostaque L. Y. (2024). Bangladesh-US relations: Managing the asymmetry in the changing global scenarios. *Journal of Bangladesh and Global Affairs*, *03*. https://doi.org/10.55875/JBGA. V3N1-2A3
31. Bose S. (2025, October 3). *US-Bangladesh ties: Ports, power, and partnerships*. https://www.orfonline.org/expert-speak/us-bangladesh-ties-ports-power-and-partnerships
32. Islam, D. M. S. (2023, June 7). Why does bangladesh matter to the united states? *THE FINANCIAL EXPRESS*. https://thefinancialexpress.com.bd/views/views/why-does-bangladesh-matter-to-the-united-states
33. Rahman, M. H. (2024, November 14). *What a second trump presidency means for bangladesh*. https://thediplomat.com/2024/11/what-a-second-trump-presidency-means-for-bangladesh/
34. Mohsin S. (2025, January 24). Trump policy shifts: Bangladesh treads tightropes. *NEWAGE*. https://www.newagebd.net/print/post/256139

35. Hossain M. (2024, October 16). Will a trump presidency impact US-Bangladesh relations?. *The Business Standard*. https://share.google/wk5wvf5BChv3M3NuX
36. Islam T. (n.d.). *Trump's critique of bangladesh and its implications for US relations*. Thearabianpost.com. https://thearabianpost.com/trumps-critique-of-bangladesh-and-its-implications-for-us-relations/?srsltid=AfmBOorx6CS18RosiwvVKTeaCvdTQ-pRhzd4H0k4sBKPvAQfIi2tn7ai
37. Datta S. (2024, august,7). *What are the ramifications of bangladesh's political turmoil for india, broader region?* Asia Pacific Foundation of Canada. https://www.asiapacific.ca/publication/explainer-bangladeshs-popular-uprising-creates-political-uncertainty
38. Chaudhari, R. R., & Solanki V. (2024, August 20). *Bangladesh: Domestic turmoil and regional insecurity*. Iiss.org. https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2024/08/bangladesh-domestic-turmoil-and-regional-insecurity/
39. Mukherjee A. (2025). Bangladesh crisis and challenges for india. *Ssrn*. https://doi.org/10.2139/ssrn.5284473
40. Koshti V. (2024, August 16). *Crisis and reform in bangladesh*. Rosalux.de. https://www.rosalux.de/en/news/id/52785/crisis-and-reform-in-bangladesh
41. Chaudhury, J. R. (2025, June 12). *Bangladesh crisis: Rising tensions, fragile governance, regional fallout*. Thesecretariat.in. https://thesecretariat.in/article/bangladesh-crisis-rising-tensions-fragile-governance-regional-fallout
42. Rasheed, D. A., & Banarjee S. (2024, August 22). *Bangladesh's political change: Implications for the indo-pacific*. https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/bangladeshs-political-change-implications-for-the-indo-pacific/
43. Ahmed M. (2025). Bangladesh at the crossroads of US-china strategic rivalry: A deep state and hegemonic influence perspective. *Ssrn*. https://doi.org/10.2139/ssrn.5815904
44. (2026, January 8). Which are the 66 global organisations the US in leaving under trump? *ALJAZEERA*. https://www.aljazeera.com/news/2026/1/8/which-are-the-66-global-organisations-the-us-is-leaving-under-trump
45. (2026, January 25). US defence strategy puts china, indo-pacific first. THE MORUNGEXPRESS. https://morungexpress.com/us-defence-strategy-puts-china-indo-pacific-first
46. Mukherji B. (2025). *US aid freeze threatens bangladesh's fragile economy and political stability*. THIS WEEK IN ASIA. https://amp.scmp.com/week-asia/politics/article/3296616/us-aid-freeze-threatens-bangladeshs-fragile-economy-and-political-stability